साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 16-22 सितंबर 2024 वर्ष-10, अंक-22

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

मोहन यादव ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा था

शिवराज ने चौंकायाः रात को पहुंचा सरकार का प्रस्ताव और सुबह केंद्र की लग गई मुहर

मध्यप्रदेश में एमएसपी पर होगी सोयाबीन की खरीदी

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने सोयबीन फसल की खरीद एमएसपी पर करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी की अनुमति मिल गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन उपज की सरकारी खरीद की मंजूरी दे चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र ने खरीफ सीजन 2024-25 में सोयाबीन पर 292 रुपए एमएसपी भी बढ़ाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रात को प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद सुबह सोयाबीन खरीदी की अनुमति दे दी गई है। एक दिन पहले ही मोहन कैबिनेट में सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा था। जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए केंद्र ने अनुमति दे दी। केंद्र की मंजूरी के बाद सोयाबीन किसानों को बड़ी राहत मिली है।

सरकारी खरीद के लिए तारीखें जारी| सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए धान और मिलेट्स की सरकारी खरीद के लिए तारीखें जारी की हैं। किसानों के लिए फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होगी और 4 अक्टूबर तक चलेगी। किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने में मदद के लिए यह व्यवस्था की गई है।

तीन राज्यों में सोयाबीन खरीद करेंगी एजेंसियां| मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों की उपज एमएसपी पर खरीदने की मंजूरी से पहले 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में सोयाबीन उपज की सरकारी खरीद की मंजूरी दे चुकी है। तीनों राज्यों में सोयाबीन खरीद के लिए 2 सहकारी एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सीएम मोहन बोले- समर्थन मूल्य 4,892 रुपए क्विंटल

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों के हित में कृत-संकल्पित मोदी सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। केन्द्र द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4892 रुपए तय किया गया है। प्रदेश के किसान सोयाबीन के मूल्य को लेकर काफी चिंतित थे। किसानों के हित में लिए गए निर्णय के लिए केन्द्र का मप्र की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं।

परिसीमन आयोग का गठनः बदल जाएगा जिलों का नक्शा

मप्र के जिलों की सीमाओं को लेकर कई विसंगतियां

अब नए सिरे से तय होंगी संभाग-जिलों की सीमाएं

- सीएम ने किया बड़ा एलान-सीमाओं का होगा पुनर्निर्धारण
- सेवानिवृत्त अफसर मनोज श्रीवास्तव होंगे आयोग के अध्यक्ष
- परिसीमन आयोग जिलों, संभागों की सीमाओं का लेगा जायजा
- परिसीमन आयोग एक साल में देगा रिपोर्ट
- नए जिलों, संभागों की करेगा अनुशंसा, प्रदेश में अभी 55 जिले, 10 संभाग
- मप्र में अभी कुल 428 तहसील, -12 तहसीलों को जिला बनाने की मांग

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में नए जिला और तहसील बनने के कारण सीमाएं घट-बढ़ गई हैं। कोई संभाग बहुत बड़ा हो गया तो कोई छोटा। यही स्थिति जिलों को लेकर भी है। इससे आमजन और राजस्व प्रशासन में आ रही परेशानियों को देखते हुए संभाग, जिला और तहसील की सीमाओं को पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार ने परिसीमन आयोग बनाया है। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को इसका सदस्य बनाया है, जो संभाग और जिला का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। अन्य दो सदस्य बाद में नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आयोग बनाने की जानकारी देते हुए कहा कि जब हमने सरकार बनाई, तो इस बात पर ध्यान दिया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं। गौरतलब है कि सागर जिले की बीना तहसील को जिला घोषित किए जाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश की एक दर्जन तहसीलों को जिला बनाने की मांग उठ रही है।

कई संभाग बहुत छोटे

जिले तो बढ़ गए, लेकिन जिलों की सीमाओं को लेकर कई विसंगतियां हैं। सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें बड़ी कठिनाइयां हैं। कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। इन्हें दूर करने के लिए परिसीमन आयोग बनाया है। इसके माध्यम से आस-पास के स्थानों को एक जिले से जोड़कर व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। संभागों और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा।

जनता से मांगे सुझाव

राज्य सरकार ने पुलिस थानों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है। यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से लाभकारी होगा। सरकार ने जनता से आयोग को अपने सुझाव देने का आह्वान किया है। सरकार के इस फैसले आने वाले दिनों में कई जिलों की सीमाएं बदल जाएंगी।

सरकार का अंतिम फैसला

आयोग राज्य के सभी संभागों, जिलों की सीमाओं का जायजा लेगा। जिलों, संभागों का निरीक्षण करके आमजन और प्रशासन की सहूलियत के नजरिए से उनकी सीमाओं का उचित निर्धारण भी करेगा। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार अंतिम फैसला लेगी।

हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए नए परिसीमन आयोग का गठन किया है। जिलों और संभागों का पुनः परीक्षण कर, हम जनता की भलाई के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की नींव रख रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर कोना प्रगति की ओर बढ़े।

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

सोयाबीन पर आयात शुल्क बढ़ाने से किसानों को फायदा

शिवराज बोले-मार्केट में बढ़ेगी मांग

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए गए केंद्र के अहम फैसलों पर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। गौरतलब है कि केंद्र र ने प्याज और बासमती चावल के अलावा सोयाबीन और तिलहन की फसलों पर कई बड़े फैसले लिए हैं। जहां सरकार ने प्याज और बासमती पर एमईपी खत्म कर दिया है तो वहीं खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। दोनों ही फैसलों को किसानों के हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। निर्यात शुल्क में कमी से प्याज उत्पादक किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी और प्याज का निर्यात भी बढ़ेगा। सरकार के फैसले से किसानों के अलावा प्याज से जुड़े दूसरे सेक्टर को भी सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर शुल्क 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में कटौती प्रभावी हो गई है। 40 फीसदी निर्यात शुल्क 4 मई से लागू था। सरकार नेरिफाइंड तेल पर भी सीमा शुल्क 20 फीसदी से बढ़ाकर 32.5 फीसदी कर दिया। शिवराज ने कहा कि मैं किसानों की ओर से प्रधानमंत्री को उनके किसान हितैषी फैसलों के लिए धन्यवाद देता हूं। सोयाबीन और तिलहन के दाम घट रहे थे और किसान इससे चिंतित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया। इससे सोयाबीन और अन्य तिलहन उत्पादक किसानों को मदद मिलेगी।

चौंकाने वाला खुलासाः विभाग की जरी सूची में सबसे ज्यादा ग्वालियर और दूसरे नंबर पर भोपाल में बकायादार

मंत्री का जिला अव्वल! प्रदेश में 14 हजार 733 करोड़ बिजली बिल बकाया

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियां बकायादारों से वसूली के लिए सख्ती बरत रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर 16 जिलों के डिफॉल्टरों की सूची भी कंपनी की तरफ से जारी की गई। इसमें कई रसूखदार लोगों के नाम भी शामिल हैं। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के गृहक्षेत्र ग्वालियर में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर हैं। प्रदेश में बिजली कंपनियों के 14 हजार 733 करोड़ बकाया है। इसमें सबसे ज्यादा ग्वालियर क्षेत्र पर बकाया है। यहां उपभोक्ताओं पर कुल 6,303 करोड़ बकाया है। वहीं, दूसरे नंबर पर 2,580 करोड़ के बकाया के साथ भोपाल है। ग्वालियर क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा 3,513 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद कृषि उपभोक्ताओं पर 1,734 करोड़। यह स्थिति तब है, जब सरकार उपभोक्ताओं को करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है। ग्वालियर में गैर घरेलू उपभोक्ताओं पर 621 करोड़ रुपए, औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 280 करोड़ रुपए और अन्य पर 156 करोड़ बकाया है। दूसरे नंबर पर भोपाल है। यहां पर घरेलू उपभोक्ताओं पर 1,467 करोड़, कृषि 740 करोड़, गैर घरेलू (वाणिज्यिक) 169 करोड़, औद्योगिक 108 करोड़ और अन्य पर 97 करोड़ बकाया है। इंदौर क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं पर 830 करोड़, कृषि उपभोक्ताओं पर 147 करोड़, गैर घरेलू वाणिज्यिक 152 करोड़, औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 260 करोड़ और अन्य पर 199 करोड़ बकाया हैं।

चाइनीज लहसुन के आयात पर रोक की मांग

लहसुन चीन के रास्ते दूसरे देशों से भारत में डंप किया गया

किसानों के विरोध में लहसुन की खरीदी बंद शाजापुर मंडी में नहीं हो रही लहसुन खरीदी

शाजापुर। जागत गांव हमार

कृषि उपज मंडी में किसान संगठन द्वारा किए गए विरोध के चलते व्यापारियों ने लहसुन की खरीदी बंद कर दी गई है। किसानों की नाराजगी भी देखी जा रही है और वह लहसुन की उपज लेकर मंडी नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि प्याज और अन्य उपज की नीलामी हुई। दरअसल, केंद्र सरकार लहसुन की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए चीन से लहसुन मंगवा रही है जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी कारण विरोध जताते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने मंडी बंद का आहवान करते हुए उपज न बेचने का निर्णय लिया था।

शाजापुर मंडी में बंद का असर– शाजापुर मंडी में इसका असर आंशिक असर देखा गया, वहीं शुजालपुर मंडी पूरी तरह से बंद रही। पूरी कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। इसको लेकर भी किसानों में असमंजस की स्थिति देखी गई। किसान प्याज और अन्य उपज लेकर पहुंच गए और नीलामी भी हुई। किसान चीन के लहसुन का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसकी खरीदी नहीं करने की मांग कर रहे हैं।

चीनी लहसुन के आयात पर प्रतिबंध

भारत में चीनी लहसुन के आयात पर कई वर्षों से प्रतिबंध है, लेकिन चीनी लहसुन के बिकने से व्यापारी और किसान नाराज हैं। आशंका है कि लहसुन चीन से तस्करी कर कंटेनरों से लाने की संभावना है और सरकार इस मामले की जांच करे और आयात बंद करें। यह भी सवाल उठाए गए हैं कि चीनी लहसुन कौन लाया है और अधिकारियों ने इसकी अनुमति क्यों दी। गोदाम में चाइनीज लहसुन पकड़े जाने की अफवाह उड़ी है। व्यापारियों को संदेह है कि भारत के प्रतिबंध की अनदेखी कर कई टन लहसुन चीन के रास्ते दूसरे देशों से भारत में डंप किया गया है।

प्रति क्विंटल 25 से 30 हजार चल रहे दाम

किसानों की मांग है कि अन्य किसी भी देश से लहसुन के आयात पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। किसानों ने कहा कि अगर चाइना व अन्य देश से लहसुन के आयात पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर किसान को आर्थिक नुकसान हुआ तो इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। वर्तमान में लहसुन की डिमांड के चलते भाव में तेजी देखी जा रही है। 25 से 30 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक भाव पहुंच गए हैं।

साल भर डिमांड, भंडारण में समस्या

लहसुन की डिमांड साल भर रहती है, लेकिन इसके मंडी में आने का समय सात से आठ महीने होता है। वर्तमान में डिमांड बनी हुई है, सप्लाई के मुताबिक मांग ज्यादा है। इसके अलावा हर महीने इसकी जरुरत रहती है। किसानों का कहना है कि लहसुन की एक खासियत है कि यह मसाला तो है, लेकिन सब्जी की तरह है, इसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। कुछ दिन में यह खराब हो जाता है। इसका स्टाक तभी किया जा सकता है, जब डिहाइड्रेशन करके लहसुन से पानी को सोख लिया जाए। इस बार उत्पादन कम हुआ है।

आत्मनिर्भर: मिल रही मौसम की सटीक जानकारी

किसान ने अपने ही खेत में बनाया मिनी मौसम केंद्र, जैविक प्रमाणीकरण के लिए पंजीयन भी

जबलपुर। जागत गांव हमार

जबलपुर विकासखंड के ग्राम कलगुड़ी, बरेला की प्रगतिशील महिला कृषक अंशुमाला अजय धगट के जैविक फॉर्म में करीब दो माह पहले लगाए गए मिनी मौसम केंद्र का संयुक्त संचालक कृषि के एस नेताम, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के कुलसचिव आर एस सिसोदिया, उप संचालक कृषि डॉ. एसके निगम, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर के विज्ञानिक डॉ. जीएस टैगोर एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन डॉ इंदिरा त्रिपाठी ने निरीक्षण किया।

मौसम का पूर्वानुमान – किसान अंशुमाला अजय धगट ने बताया कि मिनी मौसम केंद्र से उन्हें वर्तमान एवं अगले पन्द्रह दिन के मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। वे अपने लगभग 10 एकड़ खेत का मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल में जैविक प्रमाणीकरण के लिए पंजीयन करा चुके हैं।

हर किसान द्वारा लगाया जा सकता है...

मिनी मौसम केंद्र के निरीक्षण के अवसर पर संयुक्त संचालक कृषि के एस नेताम ने बताया कि मिनी मौसम केंद्र एक छोटा यन्त्र है, जिसे हर किसान द्वारा लगाया जा सकता है । करीब 50 हजार रुपये कीमत का सॉफ्टवेयर आधारित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन (मिनी मौसम केंद्र) सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, हवा की गति, हवा की दिशा, हवा का तापमान, हवा में नमी, वायुदाब, वर्षा, मिटटी का तापमान, मिटटी की नमी के दो स्तर और पत्तियों पर नमी जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर का पता लगाकर आगामी मौसम की जानकारी किसान को देने का कार्य करता है।

जैविक फार्म पर 110 गिर गाय

जैविक फार्म पर 110 गिर गाय हैं। इन गायों के गोबर एवं गौमूत्र से जीवामृत बनाने के लिए एडवांस लिक्विड बायोफर्टिलाइजर स्थापित किया गया है। एडवांस लिक्विड बायोफर्टिलाइजर किट में प्रतिदिन 200 लीटर जीवामृत तैयार होकर निकलता है। इसका प्रयोग वे अपने खेत में ही कर रही हैं।

किसानों के पंजीयन में समस्याओं के समाधान के लिए गठित होंगी समिति

खाद्य मंत्री बोले-किसानों को पंजीयन में नहीं हो परेशानी

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, एवं बाजरा उपार्जित करने के लिए किसानों को पंजीयन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर त्वरित समाधान किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। किसानों का पंजीयन 19 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक होगा। मंत्री ने कहा है कि पंजीयन में किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने बताया है कि तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर जिला सूचना अधिकारी एनआईसी के नेतृत्व में टीम गठित की जाएगी। एक समिति राज्य स्तर पर भी गठित होगी। राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के पंजीयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान समय-सीमा में किया जाए।

-धान, श्रीअन्न, तिलहन,दालों के रकबे में उछाल, खरीफ फसलों की बोवनी 1092 लाख हेक्टेयर

खरीफ सीजन में किसानों ने जमकर की बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

देशभर के किसानों ने खरीफ फसलों की जमकर बोवनी की है। इसके चलते अब तक खरीफ फसलों की कुल बोवनी 1092 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में की गई है, जो बीते साल की तुलना में ज्यादा है। धान की बोवनी में बंपर उछाल दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 409.50 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई है। गन्ना की खेती में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इथेनॉल में गन्ना इस्तेमाल को देखते हुए एक्सपर्ट ने जरूरत के अनुसार चीनी उत्पादन को लेकर आशंका जताई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ सीजन में फसलों की बोवनी का अब तक का आंकड़ा जारी दिया है। खरीफ फसलों में धान, श्री अन्न, तिलहन और गन्ना की बुआई सामान्य से अधिक दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल की बुआई 1092 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में की गई है। खरीफ सीजन की कुल फसलों में सर्वाधिक बोवनी धान की गई है। इस वर्ष 409.50 लाख हेक्टेयर में चावल की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 393.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब 16 लाख हेक्टेयर अधिक है। वहीं इससे पहले 2 सितंबर को जारी आंकड़ों में में 408.72 लाख हेक्टेयर में धान बोवनी की गई थी। इस हिसाब से 7 दिनों के दौरान 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने अधिक बोवनी की है।

श्रीअन्न और तिलहन का रकबा बढ़ा

इस वर्ष 188.72 लाख हेक्टेयर में श्रीअन्न यानी मोटे अनाज की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 181.74 लाख हेक्टेयर में की गई है। इस बार मोटे अनाज का क्षेत्रफर 7 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। इसी तरह इस वर्ष 192.40 लाख हेक्टेयर में तिलहन की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की 189.44 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इस हिसाब से तिलहन के रकबे में 3 लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

जमकर बोई अरहर और मूंगदाल

कृषि मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष 126.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती की गई है, जो बीते साल समान अवधि के दौरान 117.39 लाख हेक्टेयर की तुलना में 9 लाख हेक्टेयर अधिक है। अरहर दाल का रकबा बढ़कर 45.78 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इस बार किसानों ने 5 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में अरहर की बोवनी की है। मूंगदाल की बोवनी क्षेत्र में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

गन्ने ने एक्सपर्ट की चिंता बढ़ाई

गन्ना के बोवनी क्षेत्र में मामूली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष अब तक 57.68 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती की गई है। जबकि, पिछले वर्ष की इसी समय तक 57.11 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती की गई थी। इस हिसाब से करीब 57 हजार हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में गन्ना की खेती की गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि इथेनॉल के लिए गन्ना इस्तेमाल को देखते हुए जरूरत के अनुसार चीनी उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

-जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा

अच्छी बारिश से प्रदेश के अधिकांश बांध लबालब सिंचाई, पेयजल के लिए मिलता रहेगा पर्याप्त पानी

भोपाल। जागत गांव हमार

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते लगभग सभी बांध लबालब हैं। इससे सिंचाई, पेयजल एवं विद्युत उत्पादन के लिए आगामी समय में प्रदेश को पर्याप्त जल उपलब्ध होता रहेगा। प्रदेश के प्रमुख बांधों में आज की स्थिति में जलभराव की स्थिति 87 प्रतिशत से अधिक है। रिजरवायर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम में चिन्हित 282 प्रमुख बांधों में 199 बांधों में आज की स्थिति में जल भराव 90 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश के सभी प्रमुख बेसिन में बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी वर्षा के पूर्वानुमान, पानी की आवक और बांधों के गर्वनिंग लेविल के दृष्टिगत बांध के गेटों का संचालन किया जा रहा है, जिससे कहीं कोई बाढ़ की स्थिति निर्मित न हो। बांधों के खुलने और बंद होने की कार्ययोजना तैयार कर सूचना नियमित रूप से क्षेत्रीय जनता को दी जा रही है। मानसून 2024 में मध्यप्रदेश में आज दिनांक तक 929.6 मिमी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है, जो प्रदेश की औसत वर्षा से 9 प्रतिशत अधिक है। राज्य के पूर्वी हिस्से में औसत से 4 प्रतिशत अधिक एवं पश्चिमी हिस्से में औसत से 13 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में अच्छे मानसून से राज्य के प्रमुख बांधो में जल भराव की स्थिति बहुत अच्छी है। विगत वर्ष आज की स्थिति में मध्यप्रदेश में वास्तविक वर्षा 738.9 मिमी दर्ज हुई थी, जो कि औसत वर्षा से 14 प्रतिशत कम थी। पूर्वी मध्यप्रदेश में 11 प्रतिशत कम और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 16 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई थी। विगत वर्ष में आज दिनांक की स्थिति में प्रदेश के प्रमुख बांधो में 67.83 प्रतिशत औसत जलभराव था, जबकि चालू वर्षाकाल में अच्छे मानसून से प्रदेश के प्रमुख बांधो में जलभराव की स्थिति लगभग 90 प्रतिशत है।

पर्याप्त जल भंडारण हुआ

नर्मदा बेसिन अंतर्गत प्रमुख बांधों में लगभग सभी अपने पूर्ण भराव की स्थिति में है, जबलपुर जिले में स्थित बरगी बांध 101.52 प्रतिशत, रायसेन जिले में बारना 94.34 प्रतिशत, नर्मदापुरम में तवा बांध 97.50 प्रतिशत, सीहोर में कोलार बांध 99.33 प्रतिशत, खंडवा में इंदिरा सागर बांध 93.25 प्रतिशत एवं ओंकारेश्वर बांध 59 प्रतिशत जलभराव की स्थिति में है। इस प्रकार नर्मदा बेसिन में अच्छी मानसून गतिविधियों से प्रदेश में बेसिन अंतर्गत प्रमुख बांधों में पर्याप्त जल भंडारण संभव हो पाया है।

भोपाल का कोटा फुल

बेतवा बेसिन में निर्मित सभी प्रमुख वृहद बांध अपने पूर्ण भराव की स्थिति में है। इस बेसिन अंतर्गत भोपाल जिले में स्थित केरवा एवं कलियासोत बांध में 98.44 प्रतिशत जल भराव हो जाने के उपरांत इनके गेट से अगस्त माह में निकासी की गई है। इसी तरह इस बेसिन अंतर्गत अन्य प्रमुख बांधों यथा सम्राट अशोक सागर हलाली 98.68 प्रतिशत, संजय सागर बांध 99.74 प्रतिशत, राजघाट 84.09 प्रतिशत में भी पर्याप्त जल भंडारण हो गया है।

राजीव सागर 97.23 फीसदी भरा

वैनगंगा बेसिन अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख बांधो में पेंच छिंदवाड़ा 96.91 प्रतिशत, संजय सरोवर सिवनी 97.97 प्रतिशत एवं बालाघाट स्थित राजीव सागर 97.23 प्रतिशत जल भराव में है। बेसिन में औसत से अधिक वर्षा होने से सभी वृहद एवं मध्यम बांध शत-प्रतिशत भराव के निकट है। प्रदेश के गंगा बेसिन अंतर्गत निर्मित बड़ी परियोजनाओं में शहडोल स्थित बाणसागर 94.55 प्रतिशत एवं महान जिला सीधी 90.66 प्रतिशत जलभराव को प्राप्त कर चुके हैं। माही एवं ताप्ती बेसिन में निर्मित प्रमुख बांध यथा पारसडोह 97.11 प्रतिशत माही मैन और माही सब्सीडरी बांध कमश: 90.66 प्रतिशत, 97.97 प्रतिशत जल भराव को प्राप्त कर चुके हैं।

चंबल अचल भी पानी-पानी

चंबल बेसिन के प्रमुख वृहद बांध पूर्ण भराव की स्थिति के निकट पहुंच रहे हैं। गांधी सागर बांध 87.78 प्रतिशत, मोहनपुरा 93.45 प्रतिशत, कुंडलिया 92.67 प्रतिशत एवं शेष अन्य में भी पर्याप्त जल भंडारण हो गया है। प्रदेश के शेष बेसिन जैसे सिंध, केन, धसान में भी बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में अच्छी वर्षा से जल की अच्छी आवक हुई है। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंध बेसिन पर स्थित आवदा बांध 100 प्रतिशत, हरसी 102 प्रतिशत, अपर काकेटो 87 प्रतिशत, काकेटो 101 प्रतिशत, मड़ीखेड़ा 95 प्रतिशत, मोहिनी पिक अप वेयर 97.69 प्रतिशत भराव की स्थिति में है। धसान बेसिन में बाणसुजारा बांध 96.27 प्रतिशत एवं पन्ना में पवई 62.38 प्रतिशत जलभराव में है।

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पंचायतों को दी कचरा गाड़ी

अब हमारे गांव भी शहरों की तरह स्वच्छ और सुंदर बनेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश का हर गांव अब शहरों की तरह स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। स्वच्छता का यह संदेश घर-घर तक पहुंचना चाहिए। यह सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का है, अब गांव-गांव में स्वच्छता अभियान के लिए कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में सुरखी विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत को कचरा गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे हमारे गांव भी महानगरों की तरह स्वच्छ और सुंदर बने। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर जिले के राहतगढ़ में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान क्षेत्र वासियों को संबोधित करते हुए कही। मंत्री ने कहा कि शहरों की तरह अब हमारे गांव भी स्वच्छ और सुंदर बनेंगे। हर गांव में कचरा गाड़ी पहुंचेगी। आप सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। स्वच्छ गांव, स्वस्थ समाज का आधार हैं, इसलिए हर गांव को स्वच्छ बनाना है। यह कचरा गाड़ी घर-घर पहुंचेगी सभी लोग सिर्फ कचरा गाड़ी में ही कचरा डाले आसपास कचरा ना फेंके इससे हमारे गांव भी महानगरों की तरह सुंदर बन सके।

पंचायतों को दी कचरा गाड़ी

मंत्री राजपूत ने राहतगढ़ जनपद क्षेत्र की पंचायतों को कचरा गाड़ी दी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि कचरा गाड़ी का उपयोग करें और अपने घर को, गांव को और क्षेत्र को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। इस अवसर पर राहतगढ़ जनपद अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

बकरियों में संक्रामक कैप्रिन प्लुरोनिमोनिया, उपचार और उसका प्रबंधन

» डॉ. शिल्पा गजभिये
» डॉ. कंचन वलवाडकर
» डॉ. सलीम खान
» डॉ. उत्पल सचंका बोरोए
पशु औषधि विभाग , प0 चि0 प0 पा0 म0 रीवा (म0प्र0)

संक्रामक कैप्रिन प्लूरोनिमोनिया बकरियों में होने वाली एक गंभीर और अत्यधिक संक्रामक बीमारी है, जो माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम उप-प्रजाति कैप्रीपन्यूमोनिया के कारण होती है। यह बुखार, खांसी और सांस लेने मे तकलीफके साथ -साथ फाइब्रिनस प्लूरोनिमोनिया, एकतरफा फेफड़ों में हेपेटाइजेशन और प्ल्यूरल द्रव संचय जैसी रोग संबंधी विशेषताओं से चिह्नित है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक अधिसूचित बीमारी के रूप में मान्यता प्राप्त, दुनिया भर में बकरी की आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से अफ्रीका , एशिया और तुर्की में।

लगभग 30 साल पहले पहली बार पहचाने गए रोगज़नक को शुरू में माइकोप्लाज्मा प्रजाति एफ38 के रूप में जाना जाता था। जब बकरियों के झुंड को प्रभावित करता हैं, तो यह अत्यधिक उच्च रूग्णता और मृत्यु दर को जन्म दे सकता है, कभी-कभी क्रमशः 100 प्रतिशत और 90 प्रतिशत तक पहुंच जाता हैं।

सीसीपीपी की व्यापकता: भारत में, पशुओं में माइकोप्लाज्मा से संबंधित श्वसन श्वसन और जननांग संबंधी विकारों में वृद्धि हुई है। बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में एक अध्ययन ने युवा बकरियों में सीसीपीपी पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से सर्दियों और मानसून के मौसम के दौरान जब बुखार, लगातार खांसी और असामान्य फेफड़ों की आवाज़ जैसे लक्षण अधिक प्रचलित थे। माइकोप्लाज्मा मायकोइड्स को कैप्रिन प्लुरोनिमोनिया के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया था, साथ ही एम. एगलैक्टिया जैसी अन्य प्रजातियों में भी। गर्मियों के दौरान , संक्रमण उपनैदानिक बना रहता है, जिसमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, संभवत: बकरियों में बेहतर स्वास्थ्य और गतिविधि के स्तर के कारण । हालांकि , ठंड और गीले मौसम में बीमारी बढ़ जाती है, विशेष रूप से संभावित रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाली युवा बकरियों में, जिनमें से कुछ संक्रमण के कारण मर जाती है। पोस्टमॉर्टम परीक्षाओं में फेफड़ों की व्यापक क्षति और फुफ्फुसावरण रहता हैं। सीसीपीपी द्वारा उत्पन्न वैश्विक खतरे को देखते हुए, इस तेजी से फैलने वाले माइकोप्लाज्मा रोग की समझ, निदान, रोकथाम और नियंत्रण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

आर्थिक नुकसान: स्थानिक क्षेत्रों में सीसीपीपीकी वार्षिक लागत लगभग 507 मिलियन मिलियन आंकी गई है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान होता है। ये नुकसान रूग्णता , मृत्यु दर और उत्पादन प्रदर्शन में कमी के साथ-साथ रोकथाम, नियंत्रण और उपचार में शामिल खर्चों के कारण होते हैं।

रूग्णता पशुधन प्रबंधन में बाधा डालती है, उपचार लागत बढ़ाती है और व्यापार और परिवहन को प्रतिबंधित करती है। मृत्यु दर के परिणामस्वरूप मूल्यवान पशुओं का प्रत्यक्ष नुकसान होता है। विकसित देशों में, बीमार पशुओं को आमतौर पर मार दिया जाता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में यह प्रथा अक्सर संभव नहीं होती है। उत्पादन पर प्रभाव विशेष रूप से गंभीर है। उदाहरण के लिए सीसीपीपी भारत के लदाख के चांगथांग के स्वदेशी लोगो चांगपा को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, जो लगभग पूरी तरह से पश्मीना की खेती पर निर्भर हैं। वे 60 टन के राष्ट्रीय पश्मीना उत्पादन में 80 प्रतिशत (45 - 50 टन) का योगदान देते हैं। सीसीपीपी से प्रभावित बकरियों में, पश्मीना की पैदावार में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिसमें उपचार न किए गए पशुओं में लाभ - लागत अनुपात 0.79 बताया गया है, जबकि उपचारित पशुओं में यह 8.76 है।

लक्षण: सीसीपीपी के नैदानिक लक्षण आमतौर पर श्वसन प्रणाली की बीमारी से संबंधित होते है हालांकि, ये नैदानिक लक्षण प्रकोप के दौरान पशु से पशु में भिन्न हो सकते हैं और पशु की प्रजाति के अनुसार , रोग के चरण की गंभीरता चाहे वह अति तीव्र हो, तीव्र हो या जीर्ण हो। सीसीपीपी निचले श्वसन पथ (फेफड़ों सहित), फुस्फुस गुहा और संबंधित अंगों (हृदय), कभी - कभी ऊपरी श्वसन पथ और शायद ही कभी आंखों, जोड़ों, थन, यकृत और गुर्दे को प्रभावित करती है। रोग अति तीव्र, तीव्र या जीर्ण रूपों में प्रकट हो सकता है। रोग के गंभीर रूप जैसे अति तीव्र और तीव्र रूप आमतौर पर तब उत्पन्न होते हैं जब पूरी तरह से अतिसंवेदनशील झुंड रोगज़नक के संपर्क में आते हैं, जबकि जीर्ण रूप स्थानिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों में होते हैं। तीव्र रूप में, मृत्यु आमतौर पर 24 - 72 घंटो के भीतर अचानक होती है कम तीव्र या जीर्ण रूप में, और हल्के रूप से प्रभावित या तुलनात्मक रूप से प्रतिरोधी जानवरों में गंभीर फाइब्रिनस प्लुरोन्यूमोनिया के लक्षण, जिनकी विशेषता भूख न लगना, अवसाद, श्वास कष्ट , तेज बुखार (41 -44 डिग्री सेल्सियस), खांसी , नाक से स्त्राव, सुस्ती, लेटना , वक्ष दर्द, शारीरिक स्थिति का नुकसान और भारी रूग्णता (100 प्रतिशत तक) और मृत्यु दर(80-100 प्रतिशत) आम हैं।

उपचार और प्रबंधन: माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम उपप्रजाति कैप्रीपन्यूमोनिया के कारण होने वाले संक्रामक कैप्रिनप्लुरोनिमोनिया सीसीपीपी के उपचार के लिए डैनोफ्लोक्सासिन प्रभावशील हैं। मैक्रोलाइड्स, विशेष रूप से टाइलोसिन, माइकोप्लाज्मा कैप्रिकोलम उपप्रजाति कैप्रीपन्यूमोनिया (एमसीसीपी) के लिए पसंदीदा उपचार हैं, हालांकि सीसीपीपी - स्थानिक क्षेत्रों में टाइलोसिन अक्सर दुर्लभ होता हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कई वर्षों से प्रभावी रहा है, जबकि अन्य एंटीबायोटिक्स जैसे कि फ्लोरोकिनोलोन (एनरोफ्लोक्सासिन, डैनोफ्लोक्सासिन), एमिनाग्लाइकोसाइड्स (स्ट्रेप्टोमाइसिन), और प्लुरोम्यूटिलिन (टियामुलिन) का भी उपयोग किया जाता है। पहले , पेनिसिलिन जी प्रोकेन के साथ संयुक्त डायहाइड्रस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का उपयोग सीसीपीपी उपचार के लिए 30 मिलीग्राम/किलोग्राम बीडब्ल्यू इंट्रामस्क्युलर रूप से किया जाता था, स्ट्रेप्टोमाइसिन ने प्राकृतिक और प्रायोगिक दोनों संक्रमणों में बकरियों प्रभावी हैं, और इलाज की गई बकरियों में एमसीसीपी के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा विकसित हुई। टियामुलिन एक अन्य विकल्प है, जो बीमारी के शुरूआती चरणों में विशेष रूप से प्रभावी है।

भारत जैसे क्षेत्रों में बार - बार एंटीबायोटिक के उपयोग से प्रतिरोध और प्रभावशीलता में कमी आई है। बबचच की सूजन प्रकृति को देखते हुए, संयोजन चिकित्सा अधिक प्रभावी हो सकती है। इस अध्ययन में एंटीबायोटिक दवाओं-ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन (10 मिलीग्राम /किग्रा.,)/ एनरोफ्लोक्सासिन (5मिलीग्राम/किग्रा) एलर्जिक (फेनिरामाइन मैलेट, 1.0 मिलीग्राम/किग्रा) दवाओं के साथ संयोजित करने की प्रभावकारिता का आकलन किया गया ।

घोड़ों में शूल रोग (कोलिक) का कारण और उसका उपचार

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आर.के बघेरवाल
» डॉ.हेमंत मेहता
» डॉ. मुकेश शाक्य
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय महू

घोड़े में शूल रोग यकीनन सबसे भयावह बीमारी है। शूल रोग घोड़ों के लिए संभावित रूप से घातक है, हालांकि शूल रोग के अधिकांश मामलों में सरल उपचार से ही उपचार हो जाता है और बहुत कम शूल रोग घातक होते हैं। घोड़ों में 'शूल' शब्द का अर्थ केवल पेट या पेट में दर्द होता है और यह संभावना है कि अधिकांश घोड़ों को अपने जीवन में कभी न कभी शूल रोग होगा। बशर्ते कि पशु चिकित्सक से समय रहते सलाह ली जाए और उचित उपचार दिए जाएं।

घोड़े के मालिक के तौर पर यह बेहद जरूरी है कि आप शूल के लक्षणों को पहचान सकें ताकि समय रहते पशु चिकित्सक से संपर्क किया जा सके। हल्के मामलों में घोड़े में सिर्फअवसाद और भूख की कमी के लक्षण। ज्यादा दर्दनाक शूल होने पर घोड़ा बार-बार अपने पेट की ओर मुड़ सकता है, उसे थोड़ा पसीना आ सकता है और ऊपरी होंठ मुड़ सकता है, और वह आपकी अपेक्षा से जुयादा बार लेट सकता है। शूल से पीड़ति कुछ घोड़े इस तरह खिंचते हैं जैसे कि पेशाब करने की कोशिश कर रहे हों। जैसे-जैसे दर्द बढ़ता है, वे अपने अगले पैर से ज़मीन को इस तरह से पंजा मार सकते हैं जैसे कि वे कोई गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हों और अगर दर्द और बढ़ जाता है तो आपका घोड़ा अपनी पीठ के बल ज़मीन पर लोट सकता है, कभी-कभी अपने सिर के किनारों से हिंसक रूप से त्वचा को खींच सकता है। घोड़ों का पेट फूल सकता है, जो सामान्य से बड़ा और गोल दिखाई देता है और वे मल त्याग सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। यदि आपके घोड़े में शूल के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत अपने पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। शूल के अधिकांश मामलों में स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल पशु चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

शूल के कारण: शूल के कारण अलग-अलग हैं। ज्यादातर शूल पेट में गैस बनने का नतीजा होते हैं, जिसमें पेट की दीवार में खिंचाव और फैलाव के कारण दर्द होता है। दूसरे शूल गतिशीलता में वृद्धि के कारण होते हैं, जिसके कारण पेट में अत्यधिक ऐंठन होती है। इसके विपरीत, कुछ शूल सामान्य गतिशीलता के पूर्ण नुकसान के कारण होते हैं, जिससे पेट में खिंचाव और दर्द होता है। कभी-कभी बाहरी सामग्री जैसे कि बेलिंग ट्विन या प्लास्टिक बैग अवरोध में शामिल हो सकते हैं। दर्द आंत के पूर्ण अवरोध का रिणाम है जिसके पीछे गैस और इंजेस्टा का निर्माण होता है। रेत का शूल, रेत या दोमट मिट्टी के लंबे समय तक अनजाने में निगले जाने का अंतिम परिणाम है। रेत घोड़ों के बड़े बृहदान्त्र में जमा हो सकती है और समय के साथ पर्याप्त मात्रा में जमा होकर शूल का कारण बन सकती है। कृमि गंभीर और संभावित रूप से घातक शूल का कारण बन सकते हैं। सबसे ज्यादा अपराधी स्ट्रॉन्गाइल समूह के कृमि हैं। एंटरोलिथ्स वे पत्थर हैं जो समय के साथ आंत में बनते हैं और अंतत: घोड़ों की आंत को अवरुद्ध करते हैं। एक घोड़ा महीनों या वर्षों तक पेट दर्द से पीड़ित हो सकता है क्योंकि एंटरोलिथ आंत को अवरुद्ध करता है। एंटरोलिथ को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। मुड़ी हुई या बंद आंत सभी शूल रोगों में सबसे घातक होती है, और घोड़े के मालिक इससे सबसे ज्यादा डरते हैं। ये शूल तब होते हैं जब बड़ी आंत का मुक्त, बिना लंगर वाला हिस्सा अपने आप मुड़ जाता है ।

शूल का निदान: शूल से पीड़ित घोड़े का मूल्यांकन करते समय सबसे पहले यह निर्णय लिया जाता है कि घोड़ा मेडिकल शूल से पीड़ित है या सर्जिकल शूल से। मेडिकल शूल वे होते हैं जो दर्द निवारक इंजेक्शन और पेट को भिगोने पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि सर्जिकल शूल वे होते हैं जिनमें घोड़े को बचने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अन्य परीक्षण जो किए जा सकते हैं उनमें एक आंतरिक मलाशय परीक्षा, पेट में गैस और तरल पदार्थ की मात्रा का आकलन करने के लिए पेट की नली को पास करना या पेट की नली जिसमें पेट में पानी भरने वाले पेरिटोनियल द्रव का एक नमूना क्लिनिक में मूल्यांकन के लिए एकत्र किया जाता है। अन्य परीक्षणों में घोड़े के रक्त की सांद्रता निर्धारित करने के लिए रक्त परीक्षण शामिल है, जो बीमारी की गंभीरता को दर्शाता है, या आंत के आकार और स्थान का आकलन करने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड, विशेष रूप से छोटी आंत। इन परीक्षणों के परिणामों से पशुचिकित्सकों को शूल के संभावित कारण का पता लगाने के साथ-साथ उपचार में सहायता मिलती है।

शूल का उपचार: शूल के प्राथमिक उपचार में दर्द निवारक इंजेक्शन और संभवत: शामक दवाएँ देना शामिल है, जो लुढ़कने को रोकने या रोकने में मदद करती हैं। अन्य उपचार जो एक साधारण चिकित्सा शूल के लिए किए जा सकते हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स या पैराफिन तेल से पेट को भिगोना शामिल है। अधिकांश घोड़े इस उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कभी-कभी अधिक गहन चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, खासकर यदि घोड़ा मैदान में मानक उपचार के प्रति प्रतिक्रिया करने में विफल रहा हो। इस अधिक गहन उपचार में घोड़ों की चयापचय स्थिति को बनाए रखने के लिए अंत:शिरा द्रव चिकित्सा, आंत और उसकी सामग्री को हाइड्रेट करने के लिए पेट की नली द्वारा बार-बार भिगोना और आवश्यकतानुसार दवा देना शामिल है।

स्वच्छ दूध उत्पादन-समय की आवश्यकता

» डॉ. अनिल शिंदे
» डॉ. लक्ष्मी चौहान
» डॉ. प्रमोद शर्मा
» डॉ. सुमन कुमार
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र.

हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है तथा भारतीय कृषि मुख्यत: पशुओं पर आधारित है। प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में पशुपालन से संबंधित गतिविधियां तथा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे ज्यादातर किसान एक या दो गाय/भैंस पालते हैं और उस जानवर का दूध स्वयं के घर के लिए उपयोग करते हैं या पड़ोस में बेच देते हैं। धीरे-धीरे दुग्ध व्यवसाय के लिए पशुपालन करने में बढ़ोतरी हो रही है और उसमें बहुत से लोग मुनाफा भी ले रहे हैं। दूध कैल्शियम तथा प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत है और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यह एक आदर्श फूड के रूप में देखा गया है। इसके विपरीत अस्वच्छ दूध कई किस्म की बीमारियों का कारण भी हो सकता है तथा यह जल्द खराब भी हो जाता है और बाजार में इसके दाम भी कम मिलते हैं इसलिए स्वच्छ दूध आने वाले समय की जरूरत है। **स्वच्छ दूध:** दूध में कोई हानिकारक जीवाणु, धूल के कण, गोबर, मिट्टी, बाल या मक्खी इत्यादि ना हो तो उसे स्वच्छ दूध कह सकते हैं।

साफ -सुथरा वातावरण तथा गौशाला: गौशाला आरामदायक, आसानी से साफ करने योग्य और उसकी संरचना आसानी से परिवर्तित हो। जैसे कि ठंडी हवाओं से बचाया जा सके तथा गर्मियों उपयुक्त हवादार हो। पशुओं के आवास की फर्श और दीवारें, दरारों और छिद्रों से मुक्त हो क्योंकि ऐसे स्थानों पर जीवाणु एवं परजीवी पलते रहते हैं। फर्श पक्का, नमी रहित ढलावयुक्त, न फिसलने वाला और आसानी से साफ करने योग्य हो। स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था, पशु तथा आवास को साफ रखने के लिए अत्यावश्यक है। स्वच्छ एवं स्वस्थ पशु: दूहन से पहले पशुओं को धूलकण, गोबर और टूटे बालों को साफ करने के लिए खुरेश करें। थनों को अच्छी प्रकार से साफ पानी से धोना चाहिए। पशु संक्रामक रोग जैसे ब्रूसेलोसिस, टी.बी. तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित न हो। **ग्वाला और उसका स्वास्थ्य:** ग्वाला अस्वस्थ व अस्वच्छ न हो अन्यथा रोगाणुओं के फैलने का कारण बन सकता है। ग्वाले के वस्त्र स्वच्छ एवं नाखून कटे हो तथा पशु को दुहन से पहले व बाद में अच्छी निर्जीवीकरण रसायन के घोल से अच्छी तरह से हाथ साफ करना चाहिए। दूध को पूर्णता से दुहना चाहिए। संपूर्ण हथेली विधि पशु के थनों के स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी है। **साफ बर्तन:** दूध निकालने वाले बर्तनों का ऊपर से खुला भाग कम चौड़ा तथा नीचे अधिक चौड़ा हो। **स्वच्छ और स्वस्थ दूहन:** दुहन से पूर्व हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। दुहन के बाद थनों को सूखे तथा साफ कपड़े से पौछें। 8-10 मिनट में दूध दोहन करना लाभकारी होता है।

-खुदरा बाजार पहुंचते ही सब्जियों के भाव दोगुना तक पहुंचे

बारिश आई, महंगाई लाई! मटर- शिमला ने लगाया शतक, थाली से गायब सब्जी

भोपाल। जागत गांव हमार

मानसून की मार से सब्जियों के भाव आसमान पर हैं। हरी सब्जियां ही नहीं आलू, टमाटर, प्याज भी आम आदमी की जेब ढीली कर रहा है। सब्जी मंडी से लेकर खुदरा बाजार तक के दाम में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस महंगाई की रेस में पालक-सरसो साग भी पीछे नहीं है। थोक बाजार से खुदरा बाजार पहुंचते ही सब्जियों के भाव दोगुना तक पहुंच रहे हैं। इन दिनों कोई भी सब्जी खुदरा बाजार में ऐसी नहीं है जो 40-50 रुपए प्रतिकिलो से नीचे हो। ऐसे में लोगों की थाली से हरी सब्जियां ही नहीं आलू की भी कमी हो गई। महाराष्ट्र, हिमाचल और अन्य राज्यों में हो रही भारी बरसात की वजह से अधिकांश फसल बर्बाद होने का नतीजा यह है कि सब्जियों के दामों में गिरावट नहीं हो रही है। पिछले एक महीने से अधिक समय तक हरी सब्जियों के भाव 100 रुपए प्रतिकिलो के आसपास ही रह रहे हैं। यहां तक कि प्याज, मटर-टमाटर, अदरक और लहसुन भी आम लोगों की पहुंचे से बाहर हो गए हैं। इससे गृहिणियों की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है।

प्याज के भाव एक महीने बाद ही कम होने के आसार

आजादपुर मंडी के प्याज आढ़ती ललित जैन बताते हैं कि अब तो इसके भाव एक महीने बाद ही कम होने के आसार हैं। नई फसल आने के बाद ही भाव में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि किसानों के पास प्याज का स्टॉक खत्म हो गया है। आंध्रप्रदेश से आने वाला प्याज एक महीना लेट हो गया है। थोक मंडी में पुणे से आने वाले अच्छे क्लसालिटी के प्याज की बात करें तो 43-45 रुपया प्रतिकिलो है और मध्यप्रदेश से आने वाला प्याज 32-42 रुपया प्रतिकिलो है। हालांकि खुदरा बाजार में यही प्याज 70-90 रुपया प्रतिकिलो बिक रहा है। आलू का व्यापार करने वाले संदीप खंडेलवाल ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में भी आलू की कमी हो गई है। भारी बारिश की वजह से किसानों की भी मुसीबत है। थोक भाव में आलू 32-35 रुपया प्रतिकिलो बिक रहा है वहीं टमाटर 60-70 रुपए। उन्होंने बताया कि फिल्हाल सब्जियों के भाव में गिरावट की कम ही उम्मीद है। एक महीने बाद स्थिति सुधरेगी लेकिन नवरात्र के दौरान फिर से सब्जियों के भाव में तेजी आने की उम्मीद है।

सब्जी	रु. प्र.कि.	भिंडी	60-65
मटर	100	आलू	45-50
शिमला मिर्च	100	प्याज	60-90
टिंडा	60	टमाटर	60-80
घीया	50-60	पालक	80-90

-योजना में 7,307 गांव चुने गए, 5 साल चलेंगे विकास के काम

प्रदेश में पीएम आदि आदर्श ग्राम से आदिवासी गांवों के लौटे अच्छे दिन

-धार जिले में 689 गांवों में जारी हैं एक हजार 634 निर्माण कार्य

भोपाल। जागत गांव हमार

जनजातीय वर्ग के सामाजिक व आर्थिक हितों की रक्षा एवं इनकी बसाहटों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) संचालित की जा रही है। इस योजना में मध्यप्रदेश के 47 जिलों के जनजातीय बहुल 7 हजार 307 गांव चुने गए हैं। योजना के तहत पांच सालों में इन चयनित गांवों में विभिन्न क्षेणी के विकासमूलक कार्य कराए जाएंगे। योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, नरसिंहपुर, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, झाबुआ, धार एवं श्योपुर कुल 15 जिलों के 2 हजार 523 गांवों में 133 करोड़ 14 लाख 62 हजार रूपये की लागत से बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ शैक्षणिक एवं कौशल उन्नयन से जुड़े 6 हजार 50 कार्य कराए गए हैं। अनूपपुर, मुरैना, सतना, सीधी, देवास, बैतुल, श्योपुर, सीधी, मंडला, उमरिया, नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, मंदसौर एवं खरगोन कुल 15 जिलों के 1 हजार 675 गांवों में 4 हजार 27 विकास कार्यों के लिए 302 करोड़ 53 लाख 58 हजार रुपए की भेजी गई कार्ययोजना को वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब कार्ययोजना के अनुसार यहां स्वीकृत निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।

धार के गांवों में चल रहे निर्माण कार्य

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में चयनित धार जिले में प्रदेश में सर्वाधिक 689 गांवों में वर्तमान में 1 हजार 634 से अधिक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। केंद्र से इन कामों के लिए 136 करोड़ 35 लाख 12 हजार मंजूर किए गए हैं। मंजूर राशि में से 12 करोड़ 50 लाख 78 हजार रुपए की विकास राशि अब तक व्यय की जा चुकी है।

पानी की सुविधा पर फोकस

गांवों में पेयजल सुविधाओं की बेहतरी के लिए पाइपलाइन विस्तार, पानी की टंकी निर्माण, जनजातीय बसाहटों में विद्युतीकरण एवं लाइन विस्तार के कार्य, आजीविका मिशन के तहत आजीविका भवनों व सामुदायिक भवनों का निर्माण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए स्टॉप डेम/ चेक डेम निर्माण तथा अधोसंरचनात्मक विकास के लिये गांवों और शासकीय संस्थाओं तक आंतरिक पहुंच मार्ग व पुल-पुलिया निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं।

नर्सरी स्थापित कर किसान अपनी आजीविका को बनाएं सशक्त

छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, नौगांव, छतरपुर द्वारा विकसित भारत अभियान के तहत नर्सरी प्रबंधन पर सात दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ग्राम पंचायत सिगरावन कला विकासखंड नौगांव में आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र की प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वीणा पाणी श्रीवास्तव कर रही हैं और प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी) के साथ रोहित मिश्रा भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक किसान, जिनमें 25 महिला और 30 पुरुष किसान शामिल हैं। सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को नर्सरी प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना है ताकि वे व्यावसायिक रूप से नर्सरी स्थापित कर अपनी आजीविका को सशक्त बना सकें।

विभिन्न सत्र में, किसानों ने डॉ. कमलेश अहिरवार के मार्ग दर्शन में नर्सरी ट्रे का उपयोग कर सब्जियों के बीज बोए। नर्सरी ट्रे पौधों के बेहतर जड़ विकास और स्वस्थ वृद्धि के लिए सहायक है, जबकि कोकोपीट का उपयोग मिट्टी के विकल्प के रूप में किया गया। कोकोपीट पौधों को आवश्यक नमी और पोषण प्रदान करता है, जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है। इस सत्र में कृषकों को प्रो ट्रे में प्रायोगिक करके बुवाई भी कराई गई। डॉ. वीणा पाणी श्रीवास्तव द्वारा पॉली हाउस और शेडनेट तकनीकों पर चर्चा करते हुए, किसानों को बताया गया कि ये तकनीकें पौधों को अत्यधिक गर्मी, ठंड और तेज़ हवाओं से बचाने में मदद करती हैं, जिससे सालभर पौध उत्पादन संभव हो पाता है।

मानसून से परेशान थे ग्वालियर के किसान संजीव

अब बैंगन की खेती से हो रही 5 लाख कमाई

भोपाल। जागत गांव हमार

बदलते समय और जरूरत के साथ अब किसान परंपरागत खेती के अलावा उद्यानिकी (फल-सब्जियों की खेती। खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे है। इसमें राज्य और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ गया है। वहीं, किसानों के जीवन में भी अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हम आपको एक ऐसे ही किसान की कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके जीवन में सरकारी स्कीम से जुड़कर बड़ा बदलाव आया है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार विकासखंड के गोहिंदा गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान संजीव की, जो पहले धान की पारंपरिक खेती करते थे। बहुत मेहनत के बाद भी खेती से वे उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाते थे। ऊपर से अगर मॉनसून धोखा दे जाए तो फसल की पैदावार और घट जाती थी। इसके बाद संजीव ने फसल में बदलाव करने का फैसला किया तो मानो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल गई। संजीव की उन्नत किसानी में कृषि अधिकारियों और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी अहम भूमिका है।

5 लाख का शुद्ध लाभ

किसान संजीव कहते हैं कि अपने एक हेक्टेयर खेत में धान उगाने में एक लाख की लागत आती थी, जिससे लगभग एक लाख 92 हजार की आय होती थी। अगर इसमें अपना श्रम जोड़ लें तो आमदनी न के बराबर ही थी। अब उद्यानिकी विभाग की मदद से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बैंगन का उत्पादन हो रहा है। ड्रिप विथ मल्चिंग सिस्टम से बैंगन उत्पादन में 2 लाख प्रति हेक्टेयर की लागत आती है और 7 लाख रुपये की कुल आय होती है। इस प्रकार उन्हें 5 लाख की आमदनी हो रही है।

धान की फसल से कम होती थी आय

संजीव बताते हैं कि धान की फसल में ज्यादा लागत लगने के बाद भी आय कम होती थी। कई कोशिशों के बावजूद जब उम्मीद के मुताबिक आमदनी नहीं बढ़ी तब उन्होंने उद्यानिकी फसल की खेती के बारे में सोचा और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से तकनीकी मदद ली।

बैंगन की खेती आई रास

अफसरों की सलाह पर संजीव ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप विथ मल्चिंग सिस्टम से बैंगन की खेती शुरू की। इसमें उनकी लगभग एक लाख 55 हजार रुपए की लागत आई, जिसमें से योजना के तहत 70 हजार की सब्सिडी मिल गई। अब संजीव को सिर्फ एक हेक्टेयर रकबे में ड्रिप विथ मल्चिंग सिस्टम से बैंगन की खेती करने पर लागत निकालने के बाद 5 लाख का शुद्ध मुनाफा हो रहा है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए नई पहल शुरू की गई

मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए मिल रहा लोन

बालाघाट। जागत गांव हमार

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन एवं उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इस कड़ी में खादी ग्रामोद्योग मध्य प्रदेश द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। जिसमें मधुमक्खी पालन व शहद प्रसंस्करण जैसा कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है। दरअसल एमपी के बालाघाट जिले के अधिकांश क्षेत्र पर वन उपलब्ध है। ऐसे में यहां मधुमक्खी पालन प्रोजेक्ट सुगमता के साथ संचालित किया जा सकता है। इसके लिए जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना अंतर्गत बैंक से

लोन लेकर मधुमक्खी पालन/शहद प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले शहद को मप्र खादी बोर्ड भोपाल की विन्याश वेली योजना के तहत बेचा जा सकेगा। वही योजना में जरूरत होने पर शासन द्वारा हितग्राही को मधुमक्खी पालन/शहद प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकेगा।

किसान मधुमक्खी पालन के लिए लोन के लिए ऐसे करें आवेदन

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक/हितग्राही की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना चाहिए। वहीं आवेदक बालाघाट का मूल निवासी होने के अलावा कम से कम 8वीं या 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में शासन की किसी भी योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ न लिया हो एवं परिवार का कोई भी सदस्य बैंक का ऋणी नहीं होना चाहिए। इस योजना में किसी भी वगज का हितग्राही आवेदन कर सकता है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले में पदस्थ प्रभारी प्रबंधक मप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत बालाघाट से प्राप्त की जा सकती है।

संयुक्त निदेशक भारत सरकार ने किया मॉडल ग्रामों में भ्रमण

कृषि विज्ञान केंद्र में एक पेड़ मां के नाम के तहत में रोपा महोगनी का पौधा

शिवपुरी। जागत गांव हमार

दलहन विकास निदेशालय कृषि एवं किसान कलयाण मंत्रालय भारत सरकार भोपाल के संयुक्त निदेशक विपिन कुमार द्वारा गत दिवस कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी पर किया भ्रमण एवं प्राकृतिक खेती प्रदर्शन, प्रजनक बीजोत्पादन कार्यक्रम सोयाबीन प्रजाति राज सोया 24 का अवलोकन करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान में महोगनी का पौधा कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से आए रावे छात्रों की सहभागिता में कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी में रोपित किया। कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के वैज्ञानिक डॉ. जेसी गुप्ता पौध रोग विशेषज्ञ एवं डॉ. एएल बसेड़िया वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी के साथ जिले के शिवपुरी, कोलारस एवं बदरवास विकासखंडों में भ्रमण करते हुए मॉडल ऑइल सीड विलेज खरई एवं इंदार में कृषकों के प्रक्षेत्र पर प्रदर्शन तिलहनी फसलों में सोयाबीन प्रजाति राज सोया 18 एवं मूंगफली की उन्नत प्रजाति जीजेजी 32 सह ऊन्नत तकनीक का परंपरागत विधि से तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रक्षेत्र पर लगाए गए तकनीकी के साथ प्रदर्शनों का अवलोकन एवं निरीक्षण भी किया तथा आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन दिया। कृषकों एवं कृषक महिलाओं से चर्चा करते हुए उनसे फीडबैक भी लिए गए।

समस्याओं से भी संयुक्त निदेशक को कराया अवगत

कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार के साथ केन्द्र के अन्य वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के साथ केन्द्र की गतिविधियों को देखा एवं केन्द्र पर वित्तीय अभाव में हो रही समस्याओं के बारे में भी संयुक्त निदेशक को अवगत कराया तथा आवश्यक निराकरण के लिए आवेदन किया। इस अवसर पर केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एमके भार्गव ने प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत कराया। डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह वैज्ञानिक एवं प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा प्रजनक बीजोत्पादन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अन्य स्टॉफ डॉ. एनके कुशवाहा, योगेश चन्द्र रिखाड़ी, सतेन्द्र गुप्ता, आरती बंसल एवं इंद्रजीत गढ़वाल भी उपस्थित रहे।

कृषि वैज्ञानिकों ने वित्तीय कटौती पर दर्ज कराया विरोध

कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थायी रूप से संचालित करने की मांग

बैतूल। जागत गांव हमार

देशभर के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा तय सेवा शर्तों और सभी वित्तीय लाभों के परिपेक्ष्य में आज कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान संस्थान (अटारी), अंचल-9, जबलपुर के 45 वें स्थापना दिवस के दौरान इसके अतर्गत आने वाले मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों के साथ आज कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल बाजार, बैतूल वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों ने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा वित्तीय कटौती का विरोध किया। देश में लगभग 731 कृषि विज्ञान केन्द्र वत्रमान में संचालित है और लगातार चाहे भारत सरकार एवं मप्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं (अनुसंधान, प्रदशन एवं प्रसार) को कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किसानों के हित में चलाएं जा रहे हैं। आईसीएआर के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन संरचना, छुट्टी नियम, पदोन्नति नीतियां एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाले लाभों से इन कृषि विज्ञान केन्द्रों के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को वंचित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों द्वारा वर्तमान नीतियों का प्रखर विरोध किया और 'एक कृषि विज्ञान केन्द्र एक नीति' की मांग रखी। साथ ही विगत 50 वर्षों से देश में कृषि विज्ञान केन्द्र एक परियोजना के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि युक्ति संगत नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों की यह भी मांग है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों को परियोजना के रूप में न संचालित करते हुए स्थायी रूप से संचालित किए जाएं। इस मांग के परिपेक्ष्य में आज किसानों, कृषि विभाग और रावे छात्रों ने भी सहयोग किया।

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया सब्जी फसलों को कीट और रोग व्याधियों से कैसे बचाएं

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. बीएस किरार वैज्ञानिक, डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसके जाटव एवं डॉ. आईडी सिंह द्वारा दिवस ग्राम महाराजपुरा, हरपुरा, चरपुवां एवं पहाड़ी तिलवारन के कृषकों के प्रक्षेत्रों पर भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान देखा गया कि कृषक भाईयों ने सब्जी फसलें जैसे -टमाटर, मिर्च, भिंडी, प्याज, बैंगन, अदरक, अरबी एवं अन्य वर्षा कालीन फसलें लगायी गयी हैं और कुछ सब्जी फसलें रोग एवं कीट व्याधियों से प्रभावित हो रही हैं। डॉ. एसके सिंह द्वारा बताया गया कि मिर्च, टमाटर और भिंडी में पत्ती खाने वाली इल्लियों एवं रस चूसक कीटों का प्रकोप अत्यधिक है, इसके नियंत्रण हेतु बीटासाइफ्लुथ्रिन एवं इमिडाक्लोप्रिड समिश्रण की दवा 15 मिली./ली. की दर से प्रभावित फसलों पर छिड़काव करें।

फसल निगरानी दल ने भ्रमण कर किसानों को दी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र एवं उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास जिला टीकमगढ़ में संयुक्त रूप से गठित फसल निगरानी दल भरत राजवंशी (संचालक आत्मा परियोजना) डॉ. आरके प्रजापति वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र महाक खत्री वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बल्देवगढ़, अनुराग तिवारी प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जतारा, उमाशंकर यादव ब्लॉक टेक्निकल अधिकारी जतारा, एवं जयपाल छिगारहा सहायक निकरा परियोजना कृषि विज्ञान केंद्र, ने मोहनगढ़ रोड से होते हुए ग्राम कोडिया एवं ग्राम नदिया तक खेतों की स्थिति को देखा और किसानों से बात किया। वर्तमान में फसलों की स्थिति में उड़द फसल में अगेती किस्में जो पक गई है उनको किसानों को शीघ्र काटकर गहाई करने की सलाह दी गई वहीं उड़द में कुछ किस्में जल्दी ही एक सप्ताह के अंदर पक जाएगी। इसलिए मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए किसान भाई सतर्क

रहकर शीघ्र कटाई कर लें। वहीं कुछ जगह पर एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा एवं पीला चितरी रोग हैं उसके लिए किसानों को यह देखना है कि अगर फसल पक चुकी है तो ऐसे में रोग को अब नियंत्रण करने से आर्थिक रूप से नुकसान ही है और यदि अभी फसल के पकाने की अवधि में 7 - 10 दिन का विलंब है तो एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा बीमारी के लिए कार्बेन्डाजिम एवं मेन्कोजेब दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। पीला चितरी रोग एवं अन्य रस सूचक के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड 7 मिली प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द और सोयाबीन तथा मूंग के लिए यही उपाय है। मूंगफली में अगर पीला विषाणु रोग का प्रकोप हो रहा है तो भी इमिडाक्लोरोप्रिड दवा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूंगफली में अगर पत्ती बुंदकी रोग का प्रकोप है तो कार्बेन्डाजिम एवं मेन्कोजेब दवा का उपयोग कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में परम्परागत खेती अब गुजरे जमाने की बात

केले की प्राकृतिक खेती ने बदल दी किसान पूरनलाल की तकदीर

भोपाल। जागत गांव हमार

नया दौर, नया दौर की नई बात। परम्परागत खेती अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। अब दौर प्राकृतिक और उन्नत खेती का है। प्राकृतिक खेती से होने वाली उपज की आजकल भारी मांग है और इसमें फायदा भी बहुत है। प्राकृतिक खेती के इन्हीं फायदों से प्रभावित होकर किसान पूरनलाल ने अपने खेत में प्राकृतिक पद्धति से केले की खेती करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने टिश्यू कल्चर से तैयार जी-9 किस्म का केला लगाया। बड़ी मात्रा में केलों का उत्पादन कर पूरनलाल ने इस साल मात्र एक एकड़ में की गई केला पैदावार बेचकर 4 लाख रूपये कमा लिये हैं। अब तो पूरनलाल अपने सारे खेत में प्राकृतिक खेती से ही पैदावार ले रहे हैं।

पूरनलाल ने अपने खेत में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाया

किसान से केला व्यापारी बनने वाले पूरनलाल इनवाती छिन्दवाड़ा जिले के हरई ब्लॉक के भुमका गांव में रहते हैं। पूरनलाल प्राकृतिक पद्धति से केले की खेती के अलावा जहां बैंगन, टमाटर, मक्का की फसल ले रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने खेत में आम, कटहल, आंवला, सेब, एप्पल बेर, ड्रेगन फ्रूट, नीबू, संतरा और काजू के पौधे भी लगाये हैं। पूरनलाल ने अपने खेत में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगा रखा है। वह अपनी फसल के अवशेषों का समुचित प्रबंधन कर इससे खाद भी पैदा कर रहे हैं। यही खाद इनकी फसल के लिये अमृत का काम कर रही है। इससे उनके खेत की मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। साथ ही मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ रही है।

छिंदवाड़ा केला के नाम से पहचान

पूरनलाल बताते हैं कि उनके खेत का केला जबलपुर मंडी में छिन्दवाड़ा का केला नाम से प्रसिद्ध हो गया है। सामान्य केला जहां 15 से 18 रुपए प्रति किलो बिकता है। वहीं उनका प्राकृतिक पद्धति वाला केला 25 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है।

कैश क्राप से अर्जित लाभ में हुई वृद्धि

पूरनलाल प्राकृतिक खेती के अलावा कड़कनाथ मुर्गा पालन, बकरी पालन के साथ मछली पालन व्यवसाय भी कर रहे हैं। खेती की लगभग हर विधा को पूरनलाल ने अपना लिया है। पूरनलाल के पास कुल 6 एकड़ कृषि भूमि है। इसमें समन्वित तरीके से विभिन्न प्रकार के फलों व सब्जियों की पैदावार एवं लाईव कैश क्राप लेकर वे एक साल में 10 लाख का लाभार्जन कर रहे हैं। पूरनलाल की प्रगतिशीलता से क्षेत्र के दूसरे किसान बेहद प्रभावित हैं। वे भी इनसे परामर्श लेकर अब प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं।

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती...

उन्नत तरीकों से खेती-किसानी करने में है मुनाफा ही मुनाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

सोच बड़ी होनी चाहिए। रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ही प्रगतिशील विचार लिए किसान रघुवीर सिंह ने पुरानी खेती-बाड़ी में कुछ नया करने का सोची। पहले कुछ संकोच भी हुआ कि यदि नए ढंग से खेती सफल न हुई, तो परिवार कैसे पालेंगे। पर रघुवीर सिंह ने जोखिम उठाया और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से खेती करने लगे। नई सोच, नया सबेरा लेकर आती है। रघुवीर को भी अपनी प्रगतिशीलता का लाभ मिला। उन्होंने स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से एक हेक्टेयर में लहसुन की खेती की। मात्र एक हेक्टेयर में लहसुन की फसल से ही रघुवीर सिंह को अंततः 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। पानी की बचत हुई, सो अलग।

फसल मुनाफे की यह कहानी नीमच जिले की है। रघुवीर सिंह एक साधारण किसान हैं। नीमच के समीप आंवलीखेडा

गांव में रहते हैं। गांव के अन्य किसानों की तरह पहले वे भी पुराने तौर-तरीकों से खेती करते थे। पर अब उन्होंने खेती-बाड़ी के पुराने तरीकों को त्याग दिया है। नई सोच अपनाकर वे स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से खेती करके और किसानों के लिये नजीर पेश कर रहे हैं।

उद्यानिकी विभाग ने रघुवीर सिंह को 51 हजार का अनुदान दिया

वर्ष 2022-23 में रघुवीर सिंह ने मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र के लिए उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। पर ड्राप-मोर क्राप योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग ने रघुवीर सिंह को 51 हजार रुपए का अनुदान दिया और उसके खेत में स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित कराने में मदद भी की। स्प्रिंकलर लगाने के बाद रघुवीर को तीन तरह से बचत होने लगी। पानी बचने लगा। सिंचाई के लिए मजदूर भी नहीं लगाने पड़े, इससे पैसों की बचत हुई। लहसुन की फसल में कीट प्रकोप की भी रोकथाम हो गई। साथ ही लहसुन की क्वालिटी भी अच्छी हुई। बड़े आकार का लहसुन उत्पादन देखकर रघुवीर सिंह गद्गद हो गये। एक हेक्टेयर में 130 क्विंटल लहसुन हुआ। नीमच मंडी में ले जाकर बेचने पर रघुवीर को कुल 13 लाख रुपए मिले। फसल लागत घटाने पर रघुवीर को अविश्वनीय रूप से 10 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा हुआ। रघुवीर के मुनाफे से प्रेरित होकर अब दूसरे किसान भी स्प्रिंकलर से सिंचाई पद्धति से जुड़ने लगे हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने में यह पद्धति बाकई कारगर साबित हो रही है।

सरकार की मदद से आगे बढ़ने की प्रेरणा का जीवंत उदाहरण

नीमच के एक गांव की कृष्णा कीर बनीं राशन वाली लखपति दीदी

भोपाल। जागत गांव हमार

जीवनयापन के लिए घर में राशन जरूरी होता है। राशन से पोषण और इसी से मानव जीवन का अस्तित्व बना रहता है, यहां तक तो ठीक है, पर यही राशन किसी की पहचान बन जाये, तो यह अविश्वसनीय सा लगता है, पर ऐसा है। नीमच जिले के फोफलिया गांव की रहने वाली कृष्णा कीर की पहचान राशन से ही है। फोफलिया और आसपास के सभी गांवों के लोग कृष्णा को राशन वाली लखपति दीदी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं।

कृष्णा की यह पहचान ऐसे ही नहीं बनी। एक साधारण गृहणी से राशन वाली लखपति दीदी बनने तक कृष्णा ने लंबा सफर तय किया। सबसे पहले वे गांव के जय भवानी आजीविका स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। इस समूह के जरिये कृष्णा को शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन करने का दायित्व मिला। कृष्णा ने इस मौके को हाथों-हाथ लिया। अपनी योग्यता और हुनर से कुशलतापूर्वक सरकारी

राशन दुकान चलाकर कृष्णा रोजाना 700 रुपए अर्जित कर रही हैं। समूह से जुड़कर कृष्णा ने अब खुद की किराना दुकान भी शुरू कर दी है। इस किराना दुकान से कृष्णा साल में ढाई लाख से अधिक आय अर्जन कर रही हैं। इसी कारण वे राशन वाली लखपति दीदी के नाम से फेमस हो गयीं।

अब कृष्णा ने गांव में ही खुद का पक्का घर बना लिया

स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद कृष्णा की जिन्दगी में आये बदलावों की कुछ बानगी देखिये। पहले घर चलाने की परेशानी थी, अब कृष्णा ने गांव में ही खुद का पक्का घर बना लिया है। जमीन भी खरीद ली। बढ़ते काम के चलते यहां-वहां आने जाने के लिए दो पहिया वाहन भी खरीद लिया है। अब कृष्णा के बच्चें अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसके परिवार का रहन-सहन का स्तर भी सुधर गया है। कृष्णा गांव की दूसरी महिलाओं के लिये मेहनत और सरकार की मदद से आगे बढ़ने की प्रेरणा का एक जीवन्त उदाहरण बन गई हैं।

पशुपालन में हुई आसानी

लोकेश को राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना से पॉवर ड्रिवन चैफ कटर मशीन मिली

भोपाल। जागत गांव हमार

सोलह पशु... इनका पालन-पोषण... रोजाना कई बार चारा-पानी देते-देते सुबह से शाम हो जाती। काम बोझिल तो था, पर लोकेश को मन मारकर करना ही पड़ता था। सबसे से कठिनाई चारा काटने और पशुओं को खिलाने में होती थी। पर अब यह कठिनाई नहीं रही। लोकेश को सरकार की योजना से चारा कटर मशीन मिल गयी है। इससे लोकेश को चारा काटने में बेहद आसानी हो गई है। बुरहानपुर जिले के बहादरपुर गांव के रहने वाले लोकेश भालोदे खेती-किसानी करते हैं। उनके पास छोटे-बड़े मिलाकर 16 पशु हैं। इन पशुओं के लिए वे घर पर ही चारा तैयार करते हैं। पशुओं के लिए चारा लाने, काटने, परोसने और पशुओं को खिलाने में काफी समय लग जाता था। एक दिन लोकेश को पता चला कि पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों को अनुदान पर चारा कटर मशीन दी जाती है। लोकेश ने विभाग से संपर्क किया। थोड़ी औपचारिकताओं के बाद लोकेश को राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना से पॉवर ड्रिवन चैफ कटर मशीन मिल गयी।

कुट्टी कर के पशुओं को चारा खिला रहे

चैफ (चारा) कटर मशीन के उपयोग से लोकेश का काम बेहद आसान हो गया है। वे इस मशीन से कुट्टी कर के पशुओं को चारा खिला रहे हैं। चारा कटाई के लिए लोकेश को अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। इस मशीन से उसके समय और पूंजी की बचत तो हो ही रही है, पशु चारा भी अब वेस्ट नहीं होता है। इस मशीन से तैयार किया गया चारा उसके पशु बड़े चाव से खाते हैं। इससे उनका पाचन तंत्र भी मजबूत हो रहा ह ।

लोकेश को उम्मीद है कि मशीन से तैयार किया चारा खाने से अब उसे दूध उत्पादन भी पहले से अधिक होगा। लोकेश बताते हैं कि बुरहानपुर और खकनार ब्लाक के कई गांवों में पशुपालकों को यह चारा कटर मशीन दी गई है। पर इस मशीन का सबसे अधिक लाभ उसे ही हो रहा है। लोकेश बताते हैं कि इस चारा कटर मशीन का खुदरा मूल्य 22 हजार 800 रुपए है। सरकार द्वारा उसे यह मशीन 12 हजार रुपए अनुदान राशि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह से दिल्ली में की भेंट

प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ने से सांची दुग्ध संघ का होगा उन्नयन

» राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ हुआ त्रि-पक्षीय एमओयू

» मप्र में सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में सौजन्य भेंट कर प्रदेश के सहकारिता संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि गत दिवस राज्य शासन द्वारा दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन आगामी पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने पर सहमति बनी है। इस समझौते से लगभग 11 हजार गांवों के पशुपालक और दुग्ध-उत्पाद किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में इन 11 हजार गांवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं का गठन करेगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ने से सांची दुग्धसंघ का उन्नयन होगा। सांची ब्रांड को और बेहतर बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के बाद दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। प्रदेश में प्रतिदिन साढ़े पांच करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन हो रहा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जहां देश में प्रति व्यक्ति 459 ग्राम दूध प्रतिदिन की उपलब्धता है वहीं मध्यप्रदेश में यह 644 ग्राम है।

दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

अगले पांच वर्ष में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके लिए सहकारी आन्दोलन को मजबूत करने और किसानों एवं पशुपालकों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य होगा। प्रदेश के करीब चालीस हजार ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में 10 से 15 हजार ग्रामों में दुग्ध उत्पादन की स्थिति संतोषजनक है। शेष ग्रामों में विभिन्न उपायों से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे।

पशुपालन पर जोर

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देश में दुग्ध सहकारिता के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध विपणन, तकनीकी सलाह, दुग्ध प्रसंस्करण, पशु प्रजनन, पशुपालन से संबंधित आधुनिकतम तकनीकी परामर्श इत्यादि कार्य करती है। मप्र में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एकत्रीकरण की क्षमता को बढ़ाने व प्र-संस्करण एवं वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा सहयोग दिए जाने पर सहमति दी गई।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने नवाचारों को सराहा

सहकारिता मंत्री शाह ने प्रदेश शासन के इस नवाचार की सराहना की और इस दिशा में पूरे प्रदेश में काम करने का सुझाव दिया। शाह ने सहकारिता क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में केंद्र सरकार द्वारा से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय से प्रदेश के दुग्ध-उत्पादक किसानों की संपन्नता के साथ खाद्य प्र-संस्करण और कृषि आधारित उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।

उद्योग को देंगे बढ़ावा

किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के लिए न केवल कच्चे माल बल्कि उनके उत्पादों पर भी पूरी भागीदारी होगी। सीएम ने शाह को मप्र में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर आयोजित किए जा रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किए जाने के निर्णय के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

किसानों को किया जाएगा दक्ष

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मध्यप्रदेश पशुपालन और स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन के बीच त्रि-पक्षीय समझौता हुआ। डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी कवरेज का विस्तार किया जाएगा। कृषक प्रशिक्षण एवं सहकारी डेयरी कवरेज में वृद्धि के लिए सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों, स्व-सहायता समूहों और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को शामिल करेंगे। दुग्ध संकलन, परिवहन और प्र-संस्करण के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता सुधार करेंगे। मौजूदा बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग, संयंत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन और एण्ड-टू-एण्ड डिजिटलीकरण करेंगे।

रीवा-शहडोल दुग्ध संघ की होगी स्थापना

अन्य राज्यों में विपणन और विदेशों में निर्यात के लिए नीतिगत सुझाव सहित दूध और दुग्ध उत्पादों की बाजार में विपणन गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण करेंगे। मानव संसाधनों की पद स्थापना एवं क्षमता निर्माण किया जाएगा। डेयरी सहकारी समितियों के लिए चुनाव प्रक्रिया में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा। ग्वालियर और जबलपुर का दुग्ध संघ का पुनरुत्थान एवं जबलपुर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के पुनर्गठन और जबलपुर संभाग के लिए पुनर्गठित जबलपुर दुग्ध संघ और शहडोल और रीवा संभाग के लिए नए रीवा-शहडोल दुग्ध संघ की स्थापना के लिए नीतिगत सुझाव संबंधी सहमति बनी।

जिपं सीईओ इंछित गढ़पाले ने एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश

तीन सरपंचों को पद से हटाया, 19 पूर्व सरपंच और चार सचिवों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

मुरैना। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत दर्ज प्रकरणों में वर्ष 2022 से 34 प्रकरणों में तत्कालीन एवं वर्तमान सरपंच एवं सचिवों के द्वारा 1,51,79,492 रूपये की राशि से निर्माण कार्य किए गये है। 61.50 लाख शासकीय खाते में जमा की जाने से 34 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिनमें लापरवाही पाए जाने पर तीन सरपंचों को मध्यप्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया है। इसके अलावा 19 पूर्व सरपंच और 04 पंचायत सचिव पेशी पर उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने एवं सीईओ संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जनपद सीईओ को दिए है। यह जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले द्वारा दी गई है।

इनको पद से हटाया- धारा 40 के तहत पद से पृथक किए गए सबलगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत टोंगा की सरपंच ममता शर्मा, ग्राम पंचायत बत्तोखर के सरपंच अनिल रावत और मुरैना जनपद के ग्राम केंथरी के सरपंच छोटेलाल के नाम शामिल है।

इनका जारी किया गिरफ्तारी वारंट

ग्राम पंचायत कढावना के पूर्व सरपंच पूरन सिंह गुर्जर, किशोरगढ़ की पूर्व सरपंच उर्मिला, खेरली की पूर्व सरपंच मुन्नीदेवी, कोटरा की पूर्व सरपंच मुन्नीदेवी एवं सचिव रामस्वरूप शर्मा, चैना की पूर्व सरपंच सायराबानों, भैंसरोली की पूर्व सरपंच विद्यादेवी, करोला के पूर्व सरपंच राजकुमार गुर्जर, नूराबाद के पूर्व सरपंच वीरेन्द्र गुर्जर, श्यामपुर खुर्द के पूर्व सरपंच गोरीशंकर कुशवाह, लहर के पूर्व सरपंच अजय पाल सिंह, चांदपुर की पूर्व सरपंच रेखा उपाध्याय, पचेखा के पूर्व सरपंच बृखभान सिंह सिकरवार आदि द्वारा राशि जमा न करने एवं पेशियों पर उपस्थित न होने के आरोप गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत धनसुला की पूर्व सरपंच भूरी बाई तथा सचिव नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्राम पंचायत उसैथ के पूर्व सरपंच राजपाल सिंह तोमर, ग्राम पंचायत खेडाहुसैनपुर की पूर्व सरपंच हलुकाबाई, सचिव हाकिम सिंह जाटव, ग्राम पंचायत रछेड़ की पूर्व सरपंच सोपति, ग्राम पंचायत कमतरी के पूर्व सरपंच राजेन्द्र सिंह तोमर, ग्राम पचेखा के पूर्व सरपंच बृहभान सिंह सिकरवार, ग्राम पंचायत पुरावस कलॉ की पूर्व सरपंच शांति देवी एवं सचिव विश्वनाथ सिंह तोमर आदि द्वारा राशि जमा न करने एवं पेशियों पर उपस्थित न होने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने से निर्देश संबंधित जनपद सीईओ को दिए गए हैं।

सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण समय पर करें पूरा

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्माणाधीन और स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मण्डल की 83 वीं और वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 124 वीं बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को समय पर और सही ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा द्वारा परियोजनाओं की निविदा एवं स्वीकृति की जानकारी दी गई। बताया गया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों को सिंचाई परियोजनाओं से अधिक लाभ होगा।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)